

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय:—मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—103/2019 के अनुसार "आदिबद्री में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या—7253/छब्बीस—26 (2019—2020, दिनांक 22 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—103/2019 के अनुसार "आदिबद्री में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति हेतु ग्राम जुलगढ़ की ख0ख0सं0—37 के खसरा सं0—1381 कुल रकबा 0.021 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी—10(4)भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है, को आदिबद्री में आधुनिक शौचालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—103/2019 के अनुसार "आदिबद्री में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति हेतु ग्राम जुलगढ़ की ख0ख0सं0—37 के खसरा सं0—1381 कुल रकबा 0.021 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी—10(4) भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है, को आदिबद्री में आधुनिक शौचालय के निर्माण के लिए वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—260/वित्त अनुभाग—3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या—111/XXVII(7)50(39)/2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 एवं संख्या—1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विभाग के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
 - (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
 - (7) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (8) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (9) उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित भवन निर्धारित मानकों, भूकम्प विरोधी, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सौर ऊर्जा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-722/XVIII(II)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- संयुक्त सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर चमोली।
- ✓ 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।